Date | Page No.

Q. 12 नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं?
What do you mean by new economic policy?

Ans. 1991 के प्रारम्भ से, भारत आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। इन सभी आधुनिकीकरण, अनुत्पादक नियंत्रणों (Unproductive Control) को दूर करना, विदेशी निवेश सहित निजी निवेश को भी प्रोत्साहित करना एवं भारतीय अर्थ-व्यवस्था में एकजुटता लाना है। आर्थिक नीति का संबंध देश की अर्थ-व्यवस्था के मामले में राज्य के आचरण से है। आर्थिक नीति को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है —

i) व्यष्टि आर्थिक नीति —
यह आर्थिक नीति जिसका उद्देश्य साधनों के आवंटन में सुधार करना होता है। इस नीति के अन्तर्गत क्षेत्रीय नीति संबंधी नीति तथा मानव शक्ति संबंधी नीति आते हैं।

ii) समष्टि आर्थिक नीति —
यह नीति जिसका उद्देश्य साधनों का पूर्ण उपयोग तथा मूल्य स्थिरता है। इसके अन्तर्गत राजकोषीय नीति, विनिमय दर नीति, मौद्रिक नीति, तथा अन्य नीति आती है। इन सभी नीतियों का उद्देश्य अर्थ-व्यवस्था को स्थिर रखना होता है।

Teacher's Signature..................

Q.13 नई औद्योगिक नीति क्या है?
Explain new Industrial Policy.

Ans: नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत उद्योगों को लाइसेंस एवं नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ-साथ विदेशी निवेश एवं तकनीकी आयात जैसे मामलों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए गए हैं। MRTP Act एवं विदेशी मुद्रा नियम कानून (FERA) को काफी हद तक सरल बना दिया गया है तथा सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम कर दिया गया है। नई औद्योगिक नीति के प्रमुख आकर्षण निम्न हैं —

i) इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में 100% तक सीधा विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए Electronic Hardware Technology park scheme (EHTP) नाम से सरकार ने एक नयी योजना प्रारम्भ किया है।

ii) जहाँ विदेशी क्षमता द्वारा विदेशी मुद्रा की उपलब्धता निश्चित है, वहाँ पूँजीगत वस्तुओं के लिए अनुमति दी जाती है।

iii) कुछ निर्धारित उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में विदेशी तकनीक के आभाव एवं रॉयल्टी के भुगतान के लिए स्वचालित स्वीकृति योजना प्रारम्भ कर दी है।

iv) कुछ निश्चित उद्योगों को छोड़कर अनेक उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

v) औद्योगिक पंजीकृत योजनाओं को समाप्त की गई है।

Date			
Page No.			

Q.15. नयी व्यापार नीति को समझाइए।

Explain new trade policy.

Ans. नयी व्यापार नीति के अन्तर्गत विदेशी व्यापार के उदारीकरण ने देश के विदेशी व्यापार की स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन कर दिए हैं। आयात-निर्यात व्यापार को नियंत्रण के चंगुल से मुक्त कर दिया गया है। देश की आयात-निर्यात गतिविधियों पर पुराने नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया है। इन वर्षों में बहुत-सी कमजोर नीतियों को वापस ले लिया गया है। नई व्यापार नीति के प्रमुख आकर्षण निम्न हैं —

i) आयात को पूरी तरह से लाइसेंस की पकड़ से हटा दिया गया है।

ii) आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर शेष सभी वस्तुओं पर आयात शुल्क को घटाकर 30% या उससे भी कम कर दिया गया है।

iii) पूँजीगत वस्तुओं को शामिल कर अनेक मदों पर आयात शुल्क में भारी कटौती की गई है।

iv) थोड़ी-सी और अनुमति वाली मदों को छोड़कर लगभग अन्य सभी मदों के आयात में छूट दे दी गई है।

v) सस्ती दर पर निर्यात शुल्क एवं आयात कर में कटौती की गई है।